jammu-kashmir now

वर्ष : 2 अगस्त, भाग–1, 2014 पृष्ठ : 16

संपादक मंडल

आशुतोष

आयुषी केतकर

सचिन वशिष्ठ

जम्मू–कश्मीर अध्ययन केन्द्र
50, प्रवासी भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली– 110002
दूरभाष : 011–23213039, 8373995541
ईमेल– jkscdel@gmail.com
devsachinn@live.com
वेबसाईट– www.jkstudycentre.org
www.jammukashmirnow.com

नोट : लेख में दिए गए विचार लेखकों के निजी विचार हैं।
संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

विषयसूची

एक गुलमोहर लद्दाख के बलिदानियों के नाम..... 4
आशुतोष भटनागर

In Memory of our Real Icons..... 6
K G Suresh

अनुच्छेद 35–क का सच..... 9
शिवपूजन प्रसाद पाठक

First long distance train to chug out from Katra.. 11

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का सच..... 12
डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री

No more “just another unrests”!..... 13
Arvind

Arunachal, Kashmir are India's, China told..... 14

Land acquisition process going on at fast pace.. 14

Dejavu: Congress-NC Break Up..... 15
Aayushi Ketkar

Kargil War Memorial..... 16

श्रृद्धांजलि

श्रीमान विवेकानंद जी मंडल

श्रीमान विवेकानंद जी मंडल बंगाल के रहने वाले थे। वह विवेकानंद केंद्र के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। वह कुछ दिन बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में भी रहे। परम पूजनीय रज्जु भैय्या जी के साथ उनके घनिष्ठ सम्बन्ध थे। राम कृष्ण मिशन के स्वामी अशोकानंद जी ने अनंतनाग जिला स्थित नागदंडी आश्रम की प्रतिष्ठा की थी। उनके स्वर्गवास के पश्चात राम कृष्ण मिशन ने यह आश्रम विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को सौंप दिया। राम कृष्ण ने श्रीमान विवेकानंद मंडल महाराज जी को नागदंडी में इस आश्रम को सम्भालने हेतु भेज दिया। बड़ी कठिन परिस्थितियों में श्रीमान विवेकानंद जी ने (अनंतनाग) कश्मीर स्थित इस आश्रम को सम्भाल कर रखा। श्रीमान विवेकानंद जी वहां करीब दस वर्ष रहे। वह हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, बंगला, असमियां तथा भोजपुरी आदि भाषाओं में बात कर सकते थे। लगभग २ वर्षों से वह कैंसर से पीड़ित थे। १९ जुलाई को कन्याकुमारी में उनका शरीर शांत हो गया।

अगर राजनीति का विद्रूप देखना हो तो जम्मू–काश्मीर की राजनीति में देखना चाहिये। मुट्ठी भर अलगाववादी राज्य की राजनीति के मदारी बने हैं और घाटी केन्द्रित राजनीतिक दल उनकी ताल पर नाचते नजर आते हैं। यह वोटबैंक की राजनीति नहीं है क्योंकि अलगाववादी तो इस राजनीति में यकीन ही नहीं रखते हैं। वे तो मतदान का भी बहिष्कार करते हैं। फिर क्या कारण है कि राज्य के जनप्रतिनिधि जिनके मतों से चुनाव जीतते हैं उनके हितों के विपरीत अलगाववादियों के समक्ष घुटने टेकते नजर आते हैं?

हाल की घटना काश्मीरी हिन्दुओं के प्रमुख तीर्थ कौसरनाग की यात्रा पर पाबंदी लगाने की है। काश्मीरी हिन्दुओं की सुरक्षित काश्मीर वापसी के नारे तब निरर्थक नजर आने लगे जब ऑल पार्टी माइग्रेंट कॉर्डिनेशन कमेटी ने 31 जुलाई से 3 अगस्त तक कुलगाम से कौसरनाग की यात्रा की घोषणा की। कौसरनाग एक झील है जो पीरपंजाल की पहाड़ियों में स्थित है। काश्मीरी हिन्दुओं का यह एक प्रमुख तीर्थ है जहां 1980 के दशक के अंत तक निरंतर यात्रा चलती थी। आतंकवाद के दौर में लगभग 25 वर्ष तक इस यात्रा का आयोजन संभव नहीं हो सका। अब जब आतंकवाद थम गया है और काश्मीरी हिन्दुओं की वापसी की चर्चा चल पड़ी है, काश्मीरी हिन्दू वापस अपने तीर्थों की ओर रुख कर रहे हैं।

हालांकि कुलगाम के जिला उपायुक्त निसार अहमद वानी ने 21 जुलाई को ही यात्रा की अनुमति दे दी थी जिसके बाद आयोजकों ने यात्रा की तैयारियां शुरू कीं। लेकिन 30 जुलाई को देर रात यात्रा के संयोजक विनोद पंडित को अनुमति के निरस्त होने की सूचना दी गयी।

अनुमति को ऐसे समय निरस्त किया गया जबकि बहुत से यात्री जम्मू से चल कर कुलगाम पहुंच चुके थे और तड़के ही उन्हें कौसरनाग की यात्रा पर निकल जाना था। कुलगाम में इस यात्रा के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने शनिवार को कौसरनाग यात्रा के विरुद्ध काश्मीर बंद का ऐलान किया है। वहीं सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस ने यात्रा को सुरक्षित ढंग से पूरा करने के बजाय इस यात्रा का यह कह कर विरोध किया है कि इससे पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी।

सवाल उठता है कि क्या दस दिन पूर्व यात्रा की अनुमति देते समय यह पर्यावरण के विरुद्ध नहीं थी? सच तो यह है कि अलगाववादियों के इशारे पर इस यात्रा की अनुमति रोकी गयी है और यह साबित करता है कि सरकार के नीतिगत फैसलों पर भी पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी भारी पड़ते हैं।

जम्मू–काश्मीर में, जहां राज्य में सत्तारूढ़ सरकारों ने कभी भी राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया, वास्तव में इस प्रकार के आयोजन ही स्थानीय लोगों की आय का प्रमुख स्रोत बनते हैं। अलगाववादियों द्वारा इन आयोजनों के विरोध के पीछे दिये जाने वाले सांस्कृतिक खतरे के तर्क क्या जनता की रोजी–रोटी के सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं?

सभी जानते हैं कि केवल अमरनाथ यात्रा के भरोसे ही हजारों परिवारों और लाखों लोगों के साल भर पेट भरने की व्यवस्था होती है। 2008 में यात्री पड़ाव के लिये लीज पर दी गयी भूमि को भी सरकार ने अलगाववादियों के दबाव में छीनने की कोशिश की थी, हालांकि जम्मू में प्रतिक्रियास्वरूप उठ खड़े हुए जबरदस्त आंदोलन के सम्मुख सरकार और अलगाववादियों, दोनों को ही हथियार डालने पड़े थे।

कौसरनाग की यात्रा के विरुद्ध अलगाववादियों की प्रतिक्रिया के दो निहितार्थ हैं। पहला, चुनाव से ठीक पहले अलगाववादी अपनी शक्ति को तोल लेना चाहते हैं। सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस की भी इस पर नजर है क्योंकि छः साल के कुशासन से क्षुब्ध जनता के तेवर जिस तरह लोकसभा चुनावों के समय सामने आये हैं, उसमें अगर थोड़ी राहत की उम्मीद हो सकती है तो हुर्रियत के चुनाव बहिष्कार की अपील से ही हो सकती है। दूसरा, विस्थापित कश्मीरी हिन्दुओं के लिये यह सीधा संदेश है कि केन्द्र सरकार की पहल पर वे घाटी में वापस आने की उम्मीद तो पाल सकते हैं किन्तु आने के बाद उन्हें उन्हीं शर्तों पर जीना होगा जो अलगाववादी निर्धारित करेंगे। दोनों ही स्थितियां भारतीय लोकतंत्र के लिये चुनौती हैं। आगामी नवंबर में संभावित विधानसभा चुनावों में इसकी परीक्षा होगी।

एक गुलमोहर लद्दाख के बलिदानियों के नाम

● आशुतोष भटनागर

मनीषा बहन मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में आस्था ग्राम नाम से एक सेवा कार्य चलाती हैं जिसमें पिछड़े वर्गों के सैकड़ों गरीब और विकलांग बच्चों की देख–भाल की जाती है। वे सेना से सेवानिवृत हैं और करगिल के युद्ध के समय वहां मौजूद थी। उसकी स्मृतियां आज भी उनके अंतर्मन में गहरे बैठी हैं।

आस्था ग्राम के आंगन में गुलमोहर का वृक्ष है जिसे उन्होंने करगिल के बलिदानियों की स्मृति में लगाया है। गुलमोहर ही क्यों? इसलिये, क्योंकि जब मई–जून की तपती गर्मी में बाकी सभी वृक्ष अपने पत्ते तक छोड़ देते हैं, यह फूलता है। हर दिन हजारों कलियां खिलती हैं, पूरा पेड़ फूलों से लद जाता है। जब हमारे जवान करगिल की पहाड़ियों पर मातृभूमि की रक्षा के लिये अपना रक्त बहा रहे थे, बलिदान दे रहे थे, गुलमोहर का वृक्ष अपने रक्ताभ पुष्पों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था।

मनीषा बहन कागज में लिपटी, वृक्ष से कटी उन टहनियों को, जिन्हें गुलदस्ता कहते हैं, करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिये अधूरा मानती हैं। भरी जवानी में जीवन उत्सर्ग करने का साहस रखने वालों को कटी हुई डंडियां नहीं, बलिदान के प्रतीक रक्तवर्णी पुष्पों से लदा समूचा गुलमोहर ही श्रद्धांजलि अर्पित करने में सक्षम है।

मनीषा बहन के यह मनोभाव अभिव्यक्ति के अलग–अलग रूपों में प्रत्येक भारतीय में दिखते हैं। इक्कीसवीं सदी में प्रवेश का सपना देखते भारत को उसकी दहलीज पर पहुंच कर भी एक युद्ध लड़ना पड़ा। भारत ने हाल ही में परमाणु बम बनाया था और इसके तीन दिन बाद ही पाकिस्तान ने भी अपने–आप को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया था। भारत के सामरिक विशेषज्ञों ने यह जोर–जोर से कहना शुरू कर दिया था कि भारत–पाक के बीच अब परम्परागत युद्ध बीती बात हो चुका है। इस पर विश्वास करते हुए भारत ने परमाणु बम के ''पहले प्रयोग नहीं'' की नीति से अपने–आप को बांध लिया था। पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा विशेषज्ञों की इस 'डॉक्ट्रिन' पर ही चोट की। पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरिया कमांड के कमांडर परवेज मुशर्रफ ने उत्तर–पश्चिम सेक्टर में भारी घुसपैठ करा कर वहां अपने सैनिकों को तैनात कर दिया।

मई माह के दूसरे सप्ताह में करगिल की पहाड़ियों में घुसपैठियों की मौजूदगी की सूचना मिलनी शुरू हुई। अगले

कुछ दिनों में बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। २६ मई को वायुसेना ने हवाई हमला किया। २७ मई को पाक ने भारत के मिग–२१ विमान को मार गिराया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को जीवित गिरफ्तार कर गोली मारी गयी। फ्लाइट लेफ्टीनेंट नचिकेता को बंदी बनाया। २८ मई को एक और एम आई–१७ हेलीकॉप्टर पाक ने गिराया जिसमें चालक दल की मृत्यु हुई।

अगला एक सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने में गया। ६ जून को श्रीनगर–लेह मार्ग को मुक्त रखने के लिये करगिल और द्रास में हवाई हमले के साथ ही भारतीय सेना ने प्रबल आक्रमण किया। आगे के पांच सप्ताह भीषण संघर्ष के थे। भारतीय सैनिक इंच–इंच आगे बढ़ते हुए एक–एक कर चोटियों पर तिरंगा फहरा रहे थे और पाक सैनिक पीछे हटने को विवश थे।

करगिल विजय की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि जिस सीमा की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिये यह बलिदान दिया उस पर कोई समझौता संभव नहीं है।

१३ जून एक ऐतिहासिक दिन था जब आग उगलती तोपों और बन्दूकों के बीच भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल में युद्ध के मोर्चे पर पहुंच कर सैनिकों का उत्साहवर्धन किया। देश में राष्ट्रभक्ति का ज्वार उमड़ रहा था। सेना मुख्यालय को ५,१०,७२५ छात्रों की चिट्ठियां प्राप्त हुईं जिसमें अधिकांश ने सीमा पर लड़ने का अवसर दिये जाने की मांग की। ४७,२७७ नागरिकों तो १७५५ पूर्व सैनिकों ने सेना को पत्र भेजे। ३२२० अनिवासी भारतीयों ने और १२० स्वतंत्रता सेनानियों ने भी पत्र लिखे। ७२ वर्ष के एक पूर्व सैनिक ने प्रत्यक्ष युद्ध करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए मानव बम के रूप में अपना उपयोग किये जाने की प्रार्थना की। छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लकों में संचित निधि प्रधानमंत्री कोष में भेजी तो उड़ीसा की एक नवविवाहिता ने अपने विवाह के दिन ही सारे गहने करगिल के बलिदानियों के परिवारों की सहायतार्थ दान कर दिये।

१२ जुलाई को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना की वापसी की पेशकश करते हुए वाजपेयी से वार्ता का अनुरोध किया। १४ जुलाई को प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की।

इस घटना को १५ वर्ष बीत गये हैं। काल अपना चक्र पूरा कर चुका है। पाकिस्तान में मुशर्रफ और भारत में मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल पूरे कर अतीत में जा चुके हैं। पाकिस्तान में आज नवाज शरीफ पुन: निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में हैं तो भारत में वाजपेयी की विरासत संभालने वाला दल सत्तारूढ़ है। प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू और श्रीनगर के शुक्रवार को होने वाले एक दिवसीय दौरे की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने जम्मू–काश्मीर को विवादित क्षेत्र बताते हुए कहा, ''हम भारत में कथित रूप से जम्मू–कश्मीर राज्य का विलय नहीं स्वीकार करते। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है।'' प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू–कश्मीर की अवाम को अभी आत्मनिर्णय के अधिकार का इस्तेमाल करना है जिसके बारे में उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लगभग २० प्रस्तावों में भरोसा दिया गया है। पाकिस्तान के इस कथन को भारत ने पूरी तरह खारिज कर दिया है लेकिन इससे यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने न तो अपना रुख बदला है और न ही करगिल में हुए अपने अपमान से सबक सीखा है।

करगिल विजय की १५वीं वर्षगांठ के अवसर पर बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि जिस सीमा की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिये यह बलिदान दिया उस पर कोई समझौता संभव नहीं है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे और अपनी सेना को अत्याधुनिक अस्त्र–शस्त्रों से सुसज्जित करना होगा।

In Memory of our Real Icons

By K G Suresh

Symbols such as a National War Memorial and the National Military Memorial would immensely contribute towards that direction. As the famous quote aptly puts it, "Poor is the nation that has no heroes....Shameful is the one that, having them…forgets"

With the allocation of Rs100 crore for the proposed National War Memorial in the Union Budget 2014, the BJP-led NDA Government has fulfilled a long-pending demand of the Armed Forces to honour the soldiers who laid down their lives in defence of the nation since 1947.

New Delhi's India Gate, where successive Prime Ministers have been paying tributes to the nation's martyrs on Republic Day every year, was built by the alien rulers to honour the British and Indian officers and men who were killed fighting for the Union Jack during World War I and the Afghan campaign.

However, it remains a matter of shame, not just for the Armed Forces but also the nation as a whole, that even 66 years after independence, the country does not have a National War Memorial to remember the martyrs of the 1947-1948 Jammu & Kashmir operations, the 1962, 1965 and 1971 wars and the 1999 Kargil conflict. In fact, the National War Memorial was first proposed way back in the 1960s.

Earlier this year, Prime Minister Narendra Modi had attacked the then Congress-led UPA Government for dragging its feet on the National War Memorial, saying, "There is no country in the world where there is not a war memorial. India has fought several wars, thousands of our soldiers have been martyred. Should we not remember them? Should not there be a war memorial?"

The announcement during the Budget presentation by Union Finance and Defence Minister Arun Jaitley, about the proposed memorial in Princess Park near India Gate supplemented by a war museum, is in effect a materialisation of the Prime Minister's vision. Interestingly,

apart from Armed Forces personnel, one of the key activists who campaigned extensively for the National War Memorial not only in Delhi but also in different State capitals has been entrepreneur and Rajya Sabha Member Rajeev Chandrasekhar.

Much like the industrialist and former Congress MP Naveen Jindal, who vociferously advocated the cause of the Tricolour, Mr Chandrasekhar, the two-time independent MP from Bangalore, has relentlessly pursued the demand for a memorial ever since he set foot in Parliament in 2006 through numerous letters and parliamentary questions to the Defence Minister. He has also highlighted the matter outside Parliament and even approached Chief Ministers to build memorials in their respective States.

In 2009, Mr Chandrasekhar convinced the Karnataka State Government to build the National Military Memorial in Bangalore, India's very first war memorial post-independence. As the chairman of the National Military Memorial Committee, he has ensured that when inaugurated the memorial in Bangalore will be the country's first monument to honour soldiers who laid down their lives in major conflicts that took place post independence

Spread over 7.5 acres, the first memorial for our bravehearts in the heart of Bangalore boasts several unique features. The memorial park showcases the Veeragallu — Kannada for stone — recollecting the contribution of the bold and the brave. This is an imposing and traditional obelisk symbolising the strength, courage as well as conviction of martyred soldiers. The height of the monolithic granite structure is 75 feet and it weighs about 700 tonnes.

The National Military Memorial park will also have the tallest flag mast in India at 65 metres (around 213 feet). The flag mast will adorn the country's largest national flag measuring 48x78 feet. The names of more than 22,000 soldiers who laid down their lives fighting for the nation will be inscribed in plaques on the memorial's walls.

Spread over 7.5 acres, the first memorial for our bravehearts in the heart of Bangalore boasts several unique features.

In addition to this, models of weapon systems will be displayed at the 10,000 sq ft underground motivation hall in the park. Busts of war heroes such as Field Marshal SHFJ Manekshaw, Field Marshal KM Cariappa and Major Sandeep Unnikrishnan will be displayed inside the hall. Apart from being a symbol of thanksgiving, both for the citizens and the kin of the martyrs, such a memorial will also serve as beacons of inspiration for the country's younger generation.

As Mr Chandrasekhar's told the youth at the at the flag hoisting ceremony at the Bangalore memorial, the memorial should become an inspiration — not just about the brave people for whom this is being built, but in a larger way, the ideals and values that the Armed Forces represent — values of national service, commitment to the idea of a strong, progressive and united India, values of 'nation first', or, as the Armed Forces say, 'Seva

Parmo Dharma'.

"This rekindling of our national spirit is even more important today, as our nation struggles with divisions on lines of caste, religious and region. I strongly believe that our Armed Forces are the last of the few professional, secular institutions that are still driven by a sense of nationalism and duty and live and die by the simple idea of Nation First — values that unfortunately have disappeared, or are disappearing, from almost all other areas of public service", said Mr Chandrasekhar.

Most of today's youth, except those associated with some political or ideological outfits, do not relate to the idols the earlier generations admired and adored. Cricketers, film stars, pop singers and even ramp models have replaced the freedom-fighters and heroes of yore. These new age celebrities are the idols, icons and heroes of Generation X, but can they be role models?

They may inspire an aspiring model, actor or cricketer, but can they exhort one to walk that extra mile, work that extra hour, extend that helping hand and become the voice of the voiceless, to think beyond oneself and the family, for society and the country at large?

We are a young nation, with the largest youth population in the world. With religious fanatics, Maoists and drug-peddlers trying to wean away the youth in large numbers towards their nefarious activities, it becomes important, nay essential, that our youth have as role models contemporary figures whom they can emulate or at least draw inspiration from, so as to play a constructive role, both in their own and the nation's lives.

Nationalism is not about jingoism. It is about rising above the narrow confines of caste, creed, language, region, religion, and even ideology.

While symbols such as a National War Memorial and the National Military Memorial will immensely contribute in inculcating a sense of purpose and patriotism among our youth and children, it is also important that we create a modern mythology and folklore around our post-independence military heroes, in our educational curricula. If the stories of these war heroes enter our collective consciousness as a people, it is bound to inspire, uplift and revive the time honoured values of patriotism — of duty, honour and sacrifice — values that any nation needs for its survival and growth.

Nationalism is not about jingoism. It is about rising above the narrow confines of caste, creed, language, region, religion, and even ideology. Communism dreams of a borderless state, yet no other country is as passionate about its unique identity and territory as the Chinese, to the extent that they are today seen as being irredentist, whether it is on Arunachal Pradesh or the Senkaku Islands.

What India needs is positive nationalism that will enable her in overcoming divisions and scale greater heights, in terms of prosperity for her people and the well being of all nations. Setting up symbols such as a National War Memorial and the National Military Memorial are important steps in this direction. As the famous quote aptly puts it, "Poor is the nation that has no heroes....Shameful is the one that, having them…forgets." ■

(The writer is Senior Fellow and Editor with the Vivekananda International Foundation) Courtesy- The Pioneer, 28 July 2014

अनुच्छेद 35–क का सच

शिवपूजन प्रसाद पाठक

वर्तमान समय में इस मान्यता को बल मिला है कि प्रत्येक व्यक्ति के मानवमात्र होने के कारण उसे कुछ नैसर्गिक अधिकार प्राप्त होते हैं। साथ ही, नागरिक होने के कारण व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किया जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग तीन में इन्हीं मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों का मिश्रित प्रावधान है। अनुच्छेद १२ से लेकर अनुच्छेद ३५ तक इन अधिकारों का वर्णन है। इसी भाग में एक अनुच्छेद ३५—क है, लेकिन इसका स्थान भारतीय संविधान के परिशिष्ट दो रखा गया है। अनुच्छेद ३५—क के अनुसार 'भारत का संविधान लागू होने के बावजूद, जो जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी नागरिक हैं या होगें और जो राज्य सरकार के अधीन नियोजन, संपत्ति का अर्जन, राज्य में बस जाने या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सहायता के लिए कोई विशेष अधिकार या विशेषाधिकार प्रदत्त करती है, तो वह इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह भाग तीन के किसी उपबंध द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को प्रदत्त किन्हीं अधिकारों से असंगत है या उनको छीनता या न्यून करती है। इस अनुच्छेद का विश्लेषण करने से पता चलता है कि यह नैसर्गिक अधिकारों के विरोध में है और अलोकतांत्रिक है।

विधि के समक्ष असमता और विधि का असमान संरक्षण

आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था 'विधि के शासन' पर आधारित है। प्रत्येक देश के शासन का संचालन करने के लिए कुछ मौलिक दस्तावेज होते हैं। साधारण भाषा में इसे संविधान कहते हैं। विधि के शासन का प्रथम सिद्धान्त है कि विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को न तो को कोई विशेषाधिकार प्राप्त होगा और न ही ही किसी व्यक्ति को उसके अभाव के कारण निम्नतर समझा जायेगा। यह व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार भी है कि समान परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जायेगा। इसकी रक्षा के लिए संविधान लिखित आश्वासन देता है। भारत का संविधान भी इन्हीं मान्यताओं को अपने अनुच्छेद १४ में मान्यता देता है। अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद ३५—क भारत में ही दो प्रकार की विधि—व्यवस्था का निर्माण करता है। जम्मू—कश्मीर के नागरिकों को विशेष रियायत देता है। यह 'विधि के समक्ष समानता' के सिद्धान्त का उल्लंघन है।

प्रक्रिया पूर्णतः असंवैधानिक थी

संविधान में एक भी शब्द जोड़ने या घटाने की शक्ति जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है, केवल भारतीय संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय इस संशोधन की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। अनुच्छेद ३६८ संसद के संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए कहता है कि 'संविधान में किसी बात होते हुए भी, संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी'। प्रक्रिया के विषय में कहता है कि संविधान संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनःस्थापित करके ही किया जा सकेगा और जब वह विधेयक

प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर वह अपनी अनुमति देगा और तब संविधान उस विधेयक के निंबधनों के अनुसार संशोधित हो जायेगा।

लेकिन जम्मू–कश्मीर के संदर्भ में संविधान में राष्ट्रपति के कार्यपालक आदेश से १५ मई १९५४ को एक नया अनुच्छेद ३५–क ही जोड़ दिया जाता है। इस अनुच्छेद के लिए संसद में कोई बहस नहीं हुई है। यह पूरी प्रक्रिया ही अलोकतांत्रिक है।

सच को छुपाये रखने की साजिश

सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अनुच्छेद ३५–क को मौलिक अधिकारों के प्रावधान में नहीं रखा गया। इसको संविधान के परिशिष्ट दो में स्थापित किया गया। अधिकतर संविधान के जानकार चाहे वह न्यायालय से हो या विद्यालय से, इस अनुच्छेद से अनभिज्ञ है। इसका कारण इसके स्थान का निर्धारण है। जिन किताबों को सामान्य विद्यार्थी, अध्यापक या विधिवेत्ता पढ़ता है, उसमें इस अनुच्छेद का उल्लेख ही नहीं है। यह सच को छुपाने की साजिश है क्योंकि यदि २००२ में अनुच्छेद २१ में संशोधन करके २१–क जोड़ा जा सकता है, तो ३५ क को अनुच्छेद ३५ के बाद क्यों नहीं रखा गया। ■

Document of Article 35 A

APPENDIX I

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) ORDER, 1954

C.O. 48

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954.

(2) It shall come into force on the fourteenth day of May, 1954, and shall thereupon supersede the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1950.

2. The provisions of the Constitution as in force on the 20th day of June, 1964 and as amended by the Constitution (Nineteenth Amendment) Act, 1966, the Constitution (Twenty-first Amendment) Act, 1967, section 5 of the Constitution (Twenty-third Amendment) Act, 1969, the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971, section 2 of the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Act, 1971, the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, the Constitution (Thirtieth Amendment) Act, 1972, section 2 of the Constitution (Thirty-first Amendment) Act, 1973, section 2 of the Constitution (Thirty-third Amendment) Act, 1974, sections 2, 5, 6 and 7 of the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975, the Constitution (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975, the Constitution (Fortieth Amendment) Act, 1976, sections 2, 3 and 6 of the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985 and the Constitution (Sixty-first Amendment) Act, 1988 which, in addition to article 1 and article 370, shall apply in relation to the State of Jammu and Kashmir and the exceptions and modifications subject to which they shall so apply shall be as follows:—

j) After article 35, the following new article shall be added, namely:—

"35A. Saving of laws with respect to permanent residents and their rights.

—Notwithstanding anything contained in this Constitution, no existing law in force in the State of Jammu and Kashmir, and no law hereafter enacted by the Legislature of the State,—

(a) defining the classes of persons who are, or shall be, permanent residents of the State of Jammu and Kashmir; or

(b) conferring on such permanent residents any special rights and privileges or imposing upon other persons any restrictions as respects—

(i) employment under the State Government

(ii) acquisition of immovable property in the State;

(iii) settlement in the State; or

(iv) right to scholarships and such other forms of aid as the State Government may provide,

shall be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any rights conferred on the other citizens of India by any provision of this Part.".

First long distance train to chug out from Katra

About 10 days after Prime Minister Narendra Modi inaugurated 25 kilo-meters long Udhampur-Katra railway line, the first long distance train, Katra-New Delhi would start plying from Katra railway station from tomorrow. Earlier, only three DEMU trains were shuttling between Katra to Jammu and Pathankot.

As desired by Modi during inauguration of the railway line at Katra on July 4, the Railways has named the train as 'Shri Shakti Express'. Official sources told the Excelsior that 18 AC coaches train reached Katra railway station this afternoon. The AC superfast 'Shri Shakti Express' will depart from Katra daily at 10.55 pm, beginning tomorrow, and reach New Delhi at 10.45 am the next day. In the return direction, it would leave New Delhi daily at 5.30 pm and reach Katra at 5.10 am the next day.

Comprising one first AC, five AC two-tier and nine AC three-tier coaches, the train will have stoppages at Ambala Cantt, Ludhiana, Jalandhar Cantt, Pathankot Cantt, Jammu Tawi and Udhampur stations enroute in both directions.

Sources said Katra-Kalika (Chandigarh) Express would be the next train to ply from Katra railway station followed by trains from Katra to Ahmedabad (Gujarat), Bangalore (Karnataka), Mumbai (Maharashtra) and Varanasi (Uttar Pradesh).

Apart from this, Railways would extend Jammu Mail and Uttar Samparak Kranti trains, presently plying between New Delhi-Udhampur to Katra.

Apart from this, Railways Minister Sadanand Gowda had also announced Kamakhya Guwahati, Assam)-Katra Express in the budget, which would ply once a week.

Sources said new trains to Katra, announced by the Railways Minister during his address at the inauguration of Udhampur-Katra railway line along with the Prime Minister on July 4, would take time but gradually the Railways would provide connectivity to Mata Vaishno Devi pilgrims up to Katra from most parts of the country.

Prime Minister Narendra Modi had on July 4 flagged off the first train from Katra while commissioning the 25-km-long Udhampur-Katra line, built at an estimated cost of Rs 1,132.75 crore. At the function, the Prime Minister had named the train Shri Shakti Express and said such services are planned from major cities in the country. The shrine attracts about 10 million pilgrims annually. Katra station is equipped with modern facilities, including tourist guide counter, cloak room, waiting hall, VIP lounge, escalators and lifts and parking spaces.

The train connectivity to Katra is part of the ambitious Kashmir rail link project marking region's rail connectivity with the rest of the country. Now only Katra to Banihal rail link is to be constructed, which was scheduled to be completed in 2018.

(Courtesy- dailyexcelsior.com)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का सच

डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री

भारत के संघीय संविधान के अनुच्छेद ३७० को लेकर बहस कभी समाप्त नहीं होती। बहस के मोटे तौर पर दो मुद्दे रहते हैं।

१. जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा २७ अक्तूबर १९४७ को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण जम्मू कश्मीर रियासत भारत में शामिल हुई।

२. भारत के संघीय संविधान के अनुच्छेद ३७० के समाप्त हो जाने से जम्मू कश्मीर राज्य भारत का हिस्सा नहीं रहेगा।

हम अपनी बात पहले मुद्दे से ही प्रारम्भ करेंगे। जम्मू कश्मीर २७ अक्तूबर १९४७ को ही वहां के महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के कारण ही भारत में शामिल हुआ। यह प्रश्न केवल जम्मू कश्मीर रियासत से सम्बंधित नहीं है। अन्य रियासतों के बारे में भी प्राय यही कहा जाता है कि वे वहां के शासकों द्वारा १५ अगस्त १९४७ से कुछ समय पहले अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के कारण से ही भारत में शामिल हुईं। यदि केवल तर्क के लिये ही मान लिया जाये कि ये सभी रियासतें वहां के शासकों द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के कारण से ही भारत में शामिल हुईं तो प्रश्न पैदा होता है कि इस तिथि से पहले इन रियासतों की स्थिति क्या थी? इससे पहले क्या वे अलग देश थे? क्या १५ अगस्त १९४७ से पहले ग्वालियर, कपूरथला, इंदौर इत्यादि रियासतें भारत का अंग नहीं थीं? यही प्रश्न जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में लागू होता है। इसका उत्तर खोजने से ही अनुच्छेद ३७० को समझा जा सकता है। इतिहास का सामान्य विद्यार्थी भी यह मानने को तैयार नहीं होगा कि ग्वालियर, पटियाला, जम्मू या श्रीनगर कभी भारत का हिस्सा नहीं थे। वे १९४७ से पहले भी भारत का हिस्सा थे और उसके बाद भी हैं। वहां के शासकों द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन इलाकों का भारत का हिस्सा होने या न होने से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पहेली के रहस्य को समझने के लिये भारत की अवधारणा को समझ लेना जरुरी है। भारत की सीमा को रेखांकित करने वाला विष्णु पुराण, उत्तरम् यत् समुद्रस्य की बात करता है। लेकिन हम अपनी बात भारत पर हुये विदेशी आक्रमणों से प्रारम्भ करेंगे। वह भी मुगलों के आक्रमणों से ही। मुगलों ने आक्रमण करके भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया लेकिन पूरे भारत पर वे भी कब्जा नहीं कर सके। उनके शासन काल में भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन पर अलग—अलग भारतीय शासकों का ही राज्य था। मुगल अधिकृत भारत की सीमाएं भी बनती बिगड़ती रहतीं थीं क्योंकि अनेक स्थानों पर भारतीय शासक उनके कब्जाये गये क्षेत्रों को आजाद करवा लेते थे। मुगल शासन काल के अंतिम दिनों में भारत पर कब्जा कर लेने के लिये यूरोपीय जातियों में होड़ लग गई। इस को लेकर उनकी आपस में भी लड़ाइयां हुईं। इन लड़ाइयों के बाद भारत के अधिकांश हिस्से पर तो इन यूरोपीय जातियों का कब्जा हो गया लेकिन फिर भी बहुत सा हिस्सा भारतीय शासकों के पास ही रहा। इसे सूत्र रुप में निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है।

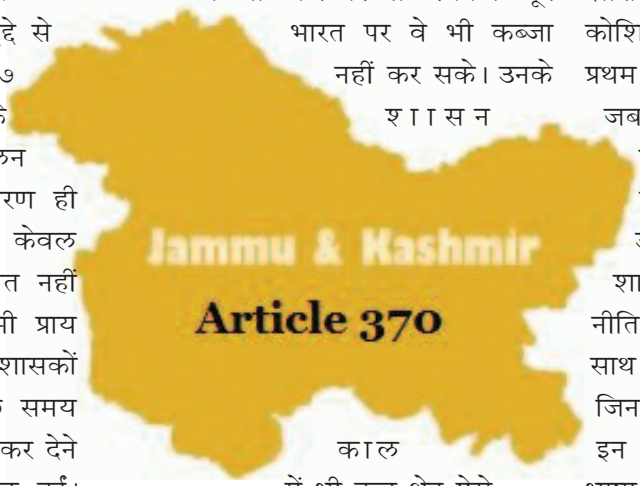

भारत= ब्रिटिश इंडिया + फ्रेंच इंडिया + पुर्तगाली इंडिया + इंडियन स्टेट्स

फ्रेंच इंडिया पर फ्रांस का कब्जा था और उस में मोटे तौर पर पुदुच्चेरी शामिल था। इसी प्रकार पुर्तगाली भारत जिसमें मोटे तौर पर गोवा दमन और दीव शामिल थे, पुर्तगाल के अधीन था। ब्रिटिश इंडिया पर १८५७ से पहले इंग्लैंड की एक व्यापारिक कम्पनी ईस्ट इंडिया कम्पनी का कब्जा था और १८५७ के बाद इंग्लैंड सरकार का कब्जा हो गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कम्पनी अपने शासन काल में, उन भारतीय क्षेत्रों पर, जो उसके कब्जे में नहीं आये थे और अभी भी भारतीयों के शासन में थे, कब्जा करने की निरंतर कोशिश करती रहती थी। १८५७ में हुये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब इंग्लैंड सरकार ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को हटा कर, उसके क्षेत्र का शासन स्वयं संभाल लिया तो उसने उन क्षेत्रों पर जो अभी भी भारतीय शासकों के पास थे, कब्जा करने की नीति का त्याग कर दिया। लेकिन उनके साथ अनेक प्रकार की संधियां कर लीं, जिनके कारण इंग्लैंड का प्रत्यक्ष नियंत्रण इन क्षेत्रों पर भी हो गया था। अंग्रेजी भाषा वाले इसे पैरामाऊंटेसी कहते हैं। भारतीय शासकों द्वारा शासित इन क्षेत्रों को भारतीय रियासतें या अंग्रेजी में इंडियन स्टेटस कहा जाता था। १९३५ में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश इंडिया और भारतीय रियासतों को मिला कर एक नई सांविधानिक व्यवस्था कायम करने की कोशिश की। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र और भारतीय रियासतों को मिला कर इंडियन डोमीनियन की स्थापना करना चाहती थी जिसमें राज्याध्यक्ष इंग्लैंड की राजाधानी द्वारा स्वीकृत गवर्नर जनरल होता। लेकिन इंग्लैंड सरकार की यह योजना सिरे नहीं चढ़ी। १९४७ में अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया से अपना प्रत्यक्ष शासन समेट कर जाने का निर्णय किया और ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। इंडियन डोमीनियन और पाकिस्तान डोमीनियन। पाकिस्तान डोमीनियन की हैसियत एक अलग देश की हो गई।

क्रमश:

No more "just another unrests"!

By Arvind

At the time when powerful and resourceful Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) is making it's way to terrorize world, the sectarian forces, once scattered, are uniting and are gaining confidence across the globe. In the very recent past Kashmir valley has witnessed many unexpected change in the behavior of it's sizable population. The Valley, which did not react on the hanging of Terrorist Afzal Guru, even after provoking by anti-nationalist of Valley for weeks, seems to surrender tactics of ISIS.

In the recent past many incidents one after another have forced to think that something is not right here in Valley. On 18 July (Friday) unruly local mob of the valley attacked Amarnath Yatris and burnt setups meant for basic survival of Yatris. Next week, historical and ancient Mata Kheer Bhawani temple was attacked on 25 July (Friday) where again local mob pelted stone and tried to disfigure it. Situation in Tral turned violent after a terrorist (a Pakistani) was killed by Indian Army. Separatist organizations of valley misguide youths of the people for Anti-Army protests when a local terrorist killed by Army but this protest after the encounter of a Pakistani terrorist has a sign of worry.

On the one hand, misguided youths of the Valley are organizing anti-Israel protests for the human right violations in Gaza, on the other, there are gatherings which support most cruel terrorist organization of recent history; ISIS. This is the same ISIS which apart from gruesome killings has ordered genital mutilation of all females between age 12 to age 42 in it's regime controlled by terror. This double standard of some youth of Valley proves that (mis) guiding force behind them is sectarian, inspiration for which is driven from Osama bin Laden and Abu Bakr al-Baghdadi.

Under the secular and democratic nature of India the protest against Israel can happen but the point of the worry is the involvement of the flag of ISIS in it. The point of concern is the effect of religious fundamentalism inspired by ISIS. Internationally ISIS is considered to be more dangerous than Al-Qaeda. It is resourceful and somehow has the ability to attract educated youth.

From last several years think tanks knew that things may worsen in the Valley after the withdrawal of the American forces. They have cautioned the Indian government in advance that terrorist-Jihadist groups may take route to Kashmir Valley after American forces withdrew from Afghanistan. After all Al-Qaeda officially has announced Kashmir as it's agenda.

Involvement of multinationals in the Islamic sectarian terroristic activity, which they like to call Jihad, is the proof of sectarian setups in all the countries and therefore India has to be little more cautious. One thing is visible that Islamic fundamentals are getting united across the globe. They quote Quran for their misdeeds. The same Quran which talks of "Ghazwa-e-Hind", a final war which has to be fought by Jihadis for the establishment of true Islamic rule, which is to be fought in "khurasan", which include a large part of north western part of India. For Islamic terrorists the Kashmir Valley of the state of Jammu-Kashmir is very crucial for so called war Ghazwa-e-Hind.

"Al-Qaeda is at the gate, and there are enough jihadis within (in India) already" writes 'Daily Mail Online' a U.K. based web portal. It's the most crucial time for set-up to look and prepare for the situation. Government should closely monitor the situation and should always be ready to act keeping all types of political correctness at bay. ■

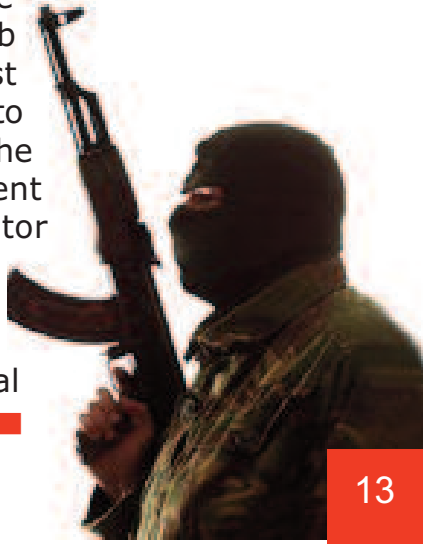

Arunachal, Kashmir are India's, China told

India has clearly told China that Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir "are integral and inalienable parts of India", Defence Minister Arun Jaitley said.

The minister told the Lok Sabha that China claims some 90,000 sq km of Indian territory in Arunachal Pradesh. "Indian territory under the occupation of China in Jammu and Kashmir is approximately 38,000 sq km," he added.

In addition, Pakistan had illegally ceded 5,180 sq km of Indian territory in its Kashmir to China, he added. "The fact that Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir are integral and inalienable parts of India has been clearly conveyed to the Chinese side on several occasions, including at the highest level," he said.

Land acquisition process going on at fast pace

The first full-fledged Indian airbase along the Line of Actual Control with China in the strategically important Ladakh region will come up at Nyoma and presently land acquisition process is going on at fast pace. The airbase would go long way in building up and strengthening existing military infrastructure along the border with the hostile neighbour.

“Soon after acquiring the required land, which is going on at fast pace, the Indian Air Force would start the construction work”, they said, adding “the construction of fighter aircraft base in Eastern Ladakh is part of Indian Air Force’s efforts to build up military infrastructure along the border with China”.

Stating that Nyoma is an important location for Army as well as Indian Air Force in the Eastern Ladakh, sources said, “though an air strip exists in Nyoma but the same cannot be used for the landing of fighter planes and heavy transport aircrafts”. “This airstrip, which overlooks a highway being used by the Chinese Army, was last used in 1960s and thereafter India stopped using it. Now, IAF wants to construct full-fledged airbase at this location by acquiring additional land”, they added.

Stating that Nyoma airbase would strategically boost defense along the Line of Actual Control with China, sources said, “this station would help in maintaining supplies and other logistics to the forces deployed to check nefarious designs of dragon”. This would be the fourth air force station in Ladakh region. At present, there are three stations-one each at Kargil, Leh and Thoise. The airbases at Kargil and Thoise are catering to the requirement of the forces deployed along the border with Pakistan. The Thoise airbase in Shyok valley is situated at an altitude of 10059 feet.

“The building of new infrastructure and strengthening of existing along the Line of Actual Control with China is of paramount importance keeping in view the aggressive attitude of neighboring country towards India”, sources said, adding “the frequent incursions by the Chinese Army into Indian side in Ladakh region particularly in Chumur and Demchok clearly indicates the dragon has not mended its ways”.

“On one side the Chinese Army is indulging in frequent incursions into Indian territory and on the other side it has objection to the inadvertent crossing of LAC by the cattle-heads of Ladakh people”, sources said while disclosing that recently Chinese Army sent a threatening letter this side after some cattle heads went to their side.

- Mohinder Verma

Dejavu : Congress-NC Break Up

By Aayushi Ketkar

The latest break-up episode of the never ending love-hate saga between the Congress and the National Conference (NC) was one that hardly created any ripples in the political landscape of J&K, let aside the Nation at large. Apart from being an oft repetitive phenomenon, it was on expected lines and based on the much-too-familiar principles of 'The Politics of Opportunism'. With elections round the corner, this move was probably the only recourse that both the parties could have taken under the 'damage control' mode, If their abysmal performance in the recent Lok Sabha elections, was any indication of the mood of the electorate to their age-old formula of promising the sky and delivering muck, the Vidhaan Sabha elections round the corner, is sure to seal the fate of non-performing parties like them that pay scant respect to the welfare of the people who brought them to power and whom they are meant to serve. .

From the very inception, this alliance was destined to fail as it had no tangible foundation. The Congress-NC alliance was neither based on ideology nor on a common agenda based on genuine concern for the safety and progress of the people of the State. The alliance came into being and survived all along with the sole purpose of safeguarding the interests of its dynastic leaders. Demeaning as it may seem, the Congress-NC alliance was never a party alliance but a personal alliance, the fabric of which got weaker with every passing generation. Starting with Jawaharlal Nehru-Sheikh Abdullah, it moved on to Rajiv Gandhi-Farooq Abdullah and now to its 3rd generation leaders, Rahul Gandhi-Omar Abdullah. The alliance had all the makings of a soap opera with more than its fair share of allegations, counter-allegations, controversies and calculations. In short, it was a deadly concoction brewing over the last 60 years, involving 3 generations of heirs of 2 of the most powerful political families of the country, the brunt of which was shouldered by a State once called 'Paradise on Earth' but now reduced to its gloomy shadow.

The Congress-NC alliance is a classic example of what an alliance should not be because when such alliances come into being, it causes irreparable and irreversible damage to the cause of national security and nation building. Jammu and Kashmir, from being one of the largest, most flourishing and progressive State of the Union of India at the time of independence, went on to become a haven for terrorist and anti-national elements in a span of half century, thanks to its selfish, sectarian leaders who filled their private coffers at the expense of public exchequer. A State that received the highest Central grants since independence stagnated in terms of infrastructural development and institutional building. The worst part is that nobody is held accountable for this gross violation of funds, nee trust.

Would this break-up be the final one? Or is it yet another electoral gimmick, with a patch-up hovering round the corner? Both the Congress and NC have seen their fortunes plummet in recent years. Will the electorate state in categorical terms 'Enough is enough'. We are not pawns but live people with hopes and aspirations of a life of dignity. Will it sound the death knell of both the parties in the forthcoming Vidhan Sabha Elections? Only time will tell. Till then, it's dejavu.■

Kargil War Memorial

Kargil war memorial, built by the Indian army following the war with neighboring Pakistan in the late nineties is frequented by travelers plying the highway connecting Srinagar to Leh. The memorial houses some of the major sequence of events that happened during the course of the war along with details of the Indian army personnel, who sacrificed their lives in the process of recapturing some of the peaks occupied by the Pakistan army; like the Tiger Hill and Tololong.

The memorial has a memento shop, selling hats, T-shirts, coffee mugs etc. But the main attraction of the whole memorial is the Sandstone wall, in the open, which has the names of all the Indian army personnel, who laid their lives during the Kargil war. Visitors to the memorial can also see from there, some of the peaks that the Indian army captured back from Pakistan.

The Kargil war memorial is by the side of the main highway going from Srinagar to Leh in Kashmir.

There were three major phases to the Kargil War. First, Pakistan infiltrated forces into the Indian-controlled section of Kashmir and occupied strategic locations enabling it to bring NH1 within range of its artillery fire. The next stage consisted of India discovering the infiltration and mobilizing forces to respond to it. The final stage involved major battles by Indian and Pakistani forces resulting in India recapturing some territory held by Pakistani forces and the subsequent withdrawal of Pakistani forces back across the Line of Control after international pressure. ■

SNEAKER

KARGIL VIJAY DIWAS